मार्च 2022 वर्ष 2, अंक 3

दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम

डी.ई.आई.–डी.ई.पी. समाचार

"जब हम बाधाओं से निपटते हैं, तो हमें साहस और लचीलेपन के छिपे हुए भंडार मिलते हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता था कि हमारे पास थे। और जब हमें असफलता का सामना करना पड़ता है तभी हमें महसूस होता है कि ये संसाधन हमेशा हमारे भीतर थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।"

–डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

विषय सूचि

कोऑर्डिनेटर की डेस्क से 2

भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 3

सूचना केन्द्रों से समाचार 5

डी.ई.आई.–डी.ई.पी. समाचार समिति 8

दयालबाग़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
(डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी)
दयालबाग़, आगरा– 282005

कोऑर्डिनेटर की डेस्क से

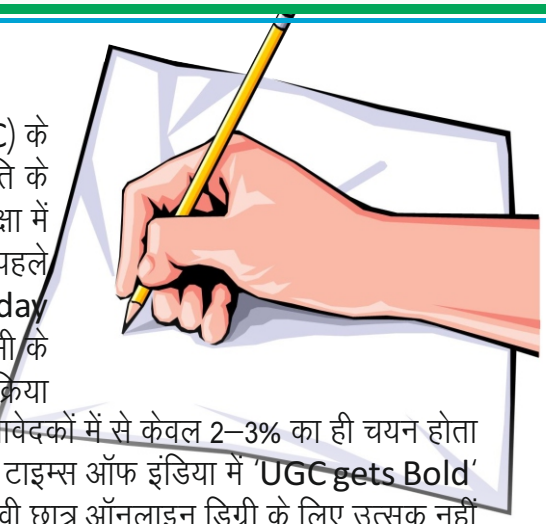

यूजीसी ने हाल ही में नर्फ (NIRF) रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल या नैक (NAAC) के 3.26 न्यूनतम ग्रेड वाले लगभग 900 स्वायत्त कॉलेजों को यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए अनुमति देकर उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा पर बड़े पैमाने पर जोर देने का निर्णय लिया है–सुविधा जो पहले केवल विश्वविद्यालयों तक विस्तारित की गई थी। मार्च 14, 2022 के Sunday Times ने इस प्रश्न को चित्रित किया कि 'क्या यह एक अच्छा विचार है?' यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार ने 'हां' कहा और आगे बताया कि 'हमारी प्रवेश प्रक्रिया उन्मूलन (elimination) में एक अभ्यास बन गई है। सर्वोत्तम संस्थानों में कुल आवेदकों में से केवल 2–3% का ही चयन होता है। यह बाकी को कहाँ छोड़ता है?' दिलचस्प बात यह है कि 22 फरवरी, 2022 के टाइम्स ऑफ इंडिया में 'UGC gets Bold' शीर्षक वाला एक संपादकीय इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर प्रदान करता है: मेधावी छात्र ऑनलाइन डिग्री के लिए उत्सुक नहीं हो सकते हैं। उनके लिए और देश के भविष्य के लिए, भारत के पास गुणवत्ता पर केंद्रित अधिक ईंट–और–मॉर्टर (Brick and Mortar) संस्थान बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि यूजीसी का प्रस्ताव निश्चित रूप से मध्यम ग्रेड वाले लोगों की मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, ये ऑनलाइन डिग्रियां भारत को सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने में मदद कर सकती हैं।

पर्यवेक्षित पूर्ण ऑनलाइन कार्यक्रम (न्यूनतम पांच पूर्ण सक्षम पर्यवेक्षकों द्वारा, मानित विश्वविद्यालयों द्वारा अनुमोदित, पिछले 40 वर्षों से अधिक के लिए केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों के बराबर) को अनिवार्य रूप से सफल होने के लिए बोनाफाइड प्रथाओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

डीईआई (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) द्वारा अनुशंसित उपरोक्त मॉडल ने हमें डीईआई (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) के मुख्यालय और इसके तत्काल पड़ोसी समुदाय का परिवेश के लिए एक व्यावहारिक स्वास्थ्य–देखभाल–आवास प्रदान करने में बिना किसी दुष्प्रभाव के कोविद–19 महामारी से दूर रहने में सक्षम बनाया है।

यूजीसी के अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि डिजिटल कक्षा भौतिक कक्षा के लिए एक आदर्श प्रतिस्थापन नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें लगता है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का समावेश शायद पहुंच (access) की समस्या को हल करने का एकमात्र विकल्प है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि शिक्षकों की नौकरियों में कोई नुकसान नहीं होगा। केवल डिजिटल विश्वविद्यालयों में उनकी भूमिका ज्ञान सामग्री के प्रसारकों से ज्ञान सामग्री के रचनाकारों में बदल जाएगी।

प्रो. अमिता रामपाल, पूर्व डीन, शिक्षा संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूजीसी के इस कदम के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनके अनुसार अनियमित ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्ता और समानता से समझौता करेगी। वह 400 इंजीनियरिंग संस्थानों का उदाहरण देती हैं जिन्हें खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा और गिरती मांग के कारण बंद करना पड़ा था। वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आलोचना करती हैं जो कि सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा को बढ़ाने की दिशा में कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाती है। इसके विपरीत, एनईपी (National Education Policy) की कुछ सिफारिशें आने वाली चीजों की दिशा को स्पष्ट करती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं को 'आसान' बनाया जाना है ताकि सभी बच्चे पास हों। पचास प्रतिशत छात्रों को स्कूल और कॉलेज दोनों स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्देशित किया जाना है।

DEI (डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी) में उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती शिक्षा अपनी स्थापना के समय से ही प्रदान की जाती रही है। शिक्षा की सलाहकार समिति (गैर–सांविधिक निकाय) के अध्यक्ष, पूज्य प्रो. पी.एस. सत्संगी साहब ने 16 मई, 2020 को घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की: वर्तमान में, एक समन्वयक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा* के लिए है, जो हमारे मामले में अन्य स्थानों से अलग है, जिसकी सुनिश्चित उपस्थिति के साथ पूरे शैक्षणिक सत्र में पर्यवेक्षण किया जाता है। कम से कम पांच अकादमिक पर्यवेक्षक (अर्थात डोमेन विशेषज्ञ), जो कि डीईआई द्वारा निर्धारित अनिवार्य है। तदनुसार, डीईआई में प्रवेश सख्ती से सीमित है, केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जेईई केंद्रों तक, जैसा कि यहां विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है (जेईई केंद्रों के विपरीत, सामान्य रूप से अध्यक्ष यूजीसी द्वारा प्रस्तावित)।

*वर्तमान में हम 288 छात्रों के कुल नामांकन के साथ डीईआई में पांच यूजीसी – हकदार कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित कर रहे हैं।

(प्रो. वी. बी. गुप्ता)

भारत में उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) प्रगति के पथ पर अग्रसर

1950–51 में भारत में उच्च शिक्षा का दृश्य काफी निराशा जनक था, 20 विश्वविद्यालयों और 695 कॉलेजों में केवल 2 लाख छात्र नामांकित थे और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) केवल 0.7 प्रतिशत था [1]। सत्तर साल बाद, वर्ष 2020 तक, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 1040 हो गई थी और कॉलेजों की संख्या लगभग 40,000 थी जब कि छात्रों का नामांकन 3.74 करोड़ था। जी ई आर अब 26.3% था जो विकसित देशों (54. 6%) की तुलना में बहुत कम था और विश्व औसत (29%), से थोड़ा कम था [2]। यह बताया गया है [3] कि यह वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि प्रासंगिक आयु वर्ग (18 से 23 वर्ष) में युवाओं की एक बड़ी आबादी उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने सफलता पूर्वक उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं की है। यह सुझाव दिया गया है कि नामांकन अनुपात की गणना अधिमानतः पात्र संख्याओं पर आधारित होनी चाहिए और योग्य नामांकन अनुपात (Eligible Enrolment Ratio) (ईईआर) की गणना भारत जैसे विकासशील देशों के लिए पहुंच (access) को मापने के लिए अधिक प्रासंगिक होगी। लेखकों द्वारा प्रदान किया गया डेटा, निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है [3]:

जी ई आर, ई.ई.आर और उन के बीच का अंतर (सभी आंकड़े प्रतिशत में)

संख्या	देश	सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2017	पात्र नामांकन अनुपात (ईईआर) 2017	अंतर (ई.ई.आर और जीईआर में) 2017
1.	यूएस	88.2	93.5	5.3
2.	जर्मनी	70.3	91.2	20.9
3.	फ्रांस	65.6	75.5	9.9
4.	यूके	60.0	63.1	3.1
5.	ब्राजील	51.3	78.6	27.2
6.	चीन	49.1	72.9	23.8
7.	इंडोनेशिया	36.4	57.7	21.2
9.	भारत	27.4	64.9	37.5
10.	दक्षिण अफ्रीका	22.4	46.6	24.2
	पाकिस्तान	9.4	43.3	33.9

यह ध्यान देने योग्य है कि ई ई आर और जी ई आर के बीच का अंतर भारत के लिए सबसे अधिक है, जो स्कूल शिक्षा की जटिल समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि ड्रॉप–आउट और विफलता दर को कम किया जा सके और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को और अधिक किफायती बनाया जा सके। भारत में जीईआर पर निम्नलिखित तालिका, में प्रस्तुत डेटा सकल नामांकन अनुपात में एक स्थिर वृद्धि दर्शाता है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक (face-to-face) उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि से और कुछ हद तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आदि के केंद्रोंसे, जो GER में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उत्पन्न होता है।

तलिकाः भारत का सकल नामांकन अनुपात (% में) (उच्च शिक्षा 18–23 वर्ष)

संख्या	लड़के	लड़कियां	भारति (weighted) औसत
2001-02	9.3	6.7	8.1
2003-04	10.6	7.7	9.2
2006-07	14.5	10.0	12.4
2009-10	17.1	12.7	15.0
2010-11	20.8	17.9	19.4
2012-13	22.3	19.8	21.1
20014-15	25.3	23.2	24.3

8 जनवरी 2012 के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह बताया गया था कि ''यूनेस्को की शिक्षा के लिए वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार, शिक्षा के छह चरण हैं। जब कि चरण एक से तीन स्कूली शिक्षा से संबंधित हैं, चरण चार व्यावसायिक शिक्षा के बारे में है और चरण पांच और छह उच्च शिक्षा के दायरे में हैं।

सख्त दृष्टिकोण उच्च शिक्षा में केवल चरण पांच और छह को शामिल करना है, लेकिन तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित व्यापक परिभाषा में–यहां तक कि चरण चार को भी शामिल किया गया है, बशर्ते कि डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स एक वर्ष से कम नहीं है।''

यह वर्ष 2010 के आस पास हुआ और 2010–11 में जीईआर में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है।

वर्ष 2018–19 में भारत में सकल नामांकन अनुपात 26.30% था और भरत कंचारला ने इस पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित दो उल्लेखनीय अवलोकन किए हैं [5]:

i. उच्च (तृतीयक) शिक्षा के लिए आयु वर्ग अंतर राष्ट्रीय स्तर पर 18–22 वर्ष है। जब अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार गणना की जाती है, तो भारत के लिए उच्च शिक्षा जीईआर 30.6% होगा। जबकि यह पाकिस्तान (9%) और बांग्लादेश (21%) से अधिक है, यह एशिया–चीन (51%), दक्षिण कोरिया (94%), मलेशिया (45%), इंडोनेशिया (36%), ईरान (70%) आदि के अन्य देशों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम है। विश्व स्तर पर, यूएसए की उच्च शिक्षा जीईआर 88% है, यू के 60% है, जर्मनी 70% पर है और कनाडा 69% है, आदि।

ii. 2018–19 में भारत में जीईआर का राज्य–वार वितरण इस प्रकार थाः

(a) बड़े राज्यों में, तमिलनाडु 49% के जीईआर के साथ पहले नम्बर पर था, उसके बाद दिल्ली (46.3%), हिमाचल प्रदेश (39.6%), उत्तराखंड (39.1%), केरल (37%) और तेलंगाना (36.2%)। राष्ट्रीय औसत से अधिक जीईआर वाले अन्य बड़े राज्यों में शामिल हैं–आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक।

(b) बड़े राज्यों में, बिहार में सबसे कम जीईआर 13.6% है, इसके बाद छत्तीसगढ़ और असम में क्रमशः 18.6% और 18.7% जीईआर हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 2018 में अखिल भारतीय औसत 26.3% से कम जीईआर वाले राज्यों में से हैं–

© राज्यों में, सिक्किम ने उच्चतम परिवर्तन दिखाया है– एक वर्ष के भीतर जीईआर में 16.5% की वृद्धि। 2017–18 में यह 37.4% था जबकि 2018–19 में यह बढ़कर 53.9% हो गया। सिक्किम 2018–19 में सबसे अधिक जीईआर वाला राज्य है।

भारत का जीईआर वर्तमान में कथित तौर पर 0.32% है [6]। प्रस्तुत आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्ष 2035 तक जीईआर = 0.50% का निर्धारित लक्ष्य काफी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

–प्रो. वी.बी. गुप्ता समन्वयक,
डीईआई दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम द्वारा संकलित

सन्दर्भः

[1] MHRD Report 2015-16 and 12th Five Year Plan Report (2012-17).

[2] Pankaj Mittal: Creating Future Ready Universities – The Indian Context, Chapter 1, in the book'Reimagining Indian Universities' Edited by Pankaj Mittal and Sistla Rama Devi Pani, Published by Association of India Universities, New Delhi in August, 2020.

[3] P. Mittal, A. Radkar, A. Kurup, A. Kharola and B. Patwardhan, Measuring Access, Quality and Relevance in higher Education, Economic & Political Weekly June 13, 2020.

[4] R.S. Bawa, University News, Jan 30 – Feb 5, 2017.

[5] https://factly.in/gross-enrolment-ratio-ger-of-higher-education-improves-but-challenges-remain%EF%BB%BF/#:~:text=Gross%20Enrolment%20Ratio%20(GER)%20of,improves%2C%20but%20challenges%20remain%EF%BB%BF&text=The%20Gross%20Enrolment%20Ratio%20(GER,GER%20for%20the%20first%20time

(Uploaded on October 22, 2019).

[6] http://timesofindia.indiatimes.com (Retrieved on 16th March, 2022).

सूचना केन्द्रों से समाचार

दयाल नगर, विशाखापत्तनम में प्रेस मीट का आयोजन

डीईआई सूचना केंद्र, दयाल नगर, विशाखापत्तनम और इंडिया यामाहा मोटर्स (प्रा.) लिमिटेड ने संयुक्त रूप से डीईआई सूचना केंद्र, दयाल नगर में 19 मार्च 2022 को दोपहिया मोटर वाहन तंत्र एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के प्रचार के लिए एक प्रेस मीट का आयोजन किया। इंडिया यामाहा मोटर्स (प्रा.) लिमिटेड दक्षिण क्षेत्रीय सेवा प्रबंधक श्री एम. प्रीतम और चार सदस्यों की उनकी टीम ने प्रेस मीट में भाग लिया। इस प्रेस मीट में केंद्र प्रभारी वी.दक्षिणा मूर्ति, शाखा सचिव डॉ.आई.राजेश वेंकट और साइट इंजीनियर श्री के.मुरलीधर राव और केंद्र के स्टाफ सदस्यों और छात्रों ने भाग लिया। इस बैठक में स्थानीय समाचार पत्रों, 'ईनाडु पेपर', 'साक्षी पेपर', 'प्रजाशक्ति पेपर', 'वर्थ पेपर' और 'आंध्र ज्योति पेपर' और टीवी के पत्रकारों ने भाग लिया। बैठक ''हे दयाल'' प्रार्थना के साथ शुरू हुई और केंद्र प्रभारी ने प्रेस वालों को दोपहिया एमवीएम के नए पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें डीईआई और दयालबाग के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। बाद में श्री. प्रीतम ने पाठ्यक्रम की सामग्री दी और यामाहा प्रशिक्षण स्कूल के बारे में संक्षेप में बताया कि यह डीईआई के सहयोग से आंध्र प्रदेश में पहला और दक्षिण भारत में 16 वां प्रशिक्षण केंद्र है। दयालबाग को एक लाइव लिंक प्रदान किया गया था और डीईआई के कोर्स इंचार्जश्री मेजर सिंह ने यामाहा कंपनी से बातचीत की। उन्होने बताया कि डीईआई द्वारा स्थापित यामाहा का यह छठा प्रशिक्षण केंद्र है। श्री. सिंह ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्र अमृतसर, राजबोरारी, टिमरनी, एमटीवी पुरम और डेढगांव में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और अब इसे विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया है। श्री. एम. प्रीतम ने आश्वासन दिया कि कोर्स पूरा होने के बाद प्लेसमेंट 100% होगा। यामाहा कंपनी और डीईआई यामाहा सेंटर्स का वीडियो भी चलाया गया और प्रेस संवाददाताओं को दिखाया गया।

इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई। प्रेस के पत्रकारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और स्थानीय समाचार पत्रों में उत्साहजनक रिपोर्ट प्रकाशित की गईं।

सूचना केंद्र रुड़की में 15 वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन

तरुणमित्र

डीईआई इन्फार्मेशन सेंटर रुड़की में "लाइट एंड साउंड शो" का हुआ आयोजन

सेवा के 15 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर रुड़की केंद्र में 20 मार्च 2022 को एक भव्य समारोह का आयोजन

किया गया, जिसमें छात्रों के माता–पिता और पूर्व छात्रों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। केंद्र की इमारत एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित थी और बहु–रंगों से झिलमिला रही थी। इस यादगार कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय की प्रार्थना और विश्वविद्यालय के गीत के साथ हुई, और उसके बाद केंद्र में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। एक ''लाइट एंड साउंड शो'' भी आयोजित किया गया था, जिसने 2007 में अपनी स्थापना से केंद्र की यात्रा को कवर किया, इस अवधि के दौरान प्रगति, गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया।

अपने संक्षिप्त संबोधन में केंद्र प्रभारी प्रो. वी. हुजूर सरन ने मुख्य अतिथि डॉ राजेश श्रीवास्तव, भौतिकी विभाग, आईआईटी रुड़की के वरिष्ठ प्रोफेसर का स्वागत किया और केंद्र की नवीनतम उपलब्धियों को साझा किया। उदाहरण के लिए, दयालबाग में शुरू किए गए एग्रोइकोलॉजी के अनुप्रयोग से प्रेरणा लेते हुए, रुड़की में एक Agro-Homeopathy based Organic Botanical HerbAl Garden (AHOBHAG अहोभाग) की स्थापना की गई है और इसे कर्मचारियों और छात्रों के संयुक्त प्रयासों से बनाए रखा जा रहा है एक संकाय सदस्य, श्रीमती वी राधा कुमारी के सक्षम मार्गदर्शन में। वर्तमान में, इस आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग सत्तर जड़ी–बूटियों और औषधीय पौधों जैसे अकरकरा, एलोवेरा, गुरु समकरु, लता कस्तूरी, लेमनग्रास, कला वासा, कालमेघ, सफेद वास, शल पर्नी, तुलसी, आदि का वर्गीकरण है। इस परियोजना की अवधारणा और शुरुआत डीईआई के पूर्व छात्र डॉ वी गुरु चरण द्वारा की गई थी।

एक और अभिनव पहल PeRmaculturE Medical Forest And Garden (PREM FAG) को ''ट्रिनिटी'' – पर्माकल्चर, जीरो–टिलेज और एग्रो–होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित किया गया है। उपरोक्त प्रथाएं जैविक खेती की लागत प्रभावी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और संपूर्ण प्रणाली बनाती हैं। जीरो टिलेज खेती में मल्चिंग पर जोर दिया जाता है, जिससे खरपतवार (weeds) और पानी की खपत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। यहां रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का स्थान होम्योपैथिक दवाओं ने ले लिया है और इन दवाओं का उपयोग कीटों और अवांछित खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

उपरोक्त अवधारणाओं के आधार पर, केंद्र में एक key hole उद्यान भी स्थापित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह अनिवार्य रूप से एक 'की–होल' के आकार में एक उठा हुआ Bed प्लांटर है। इसे एक छोटी सी जगह में बनाया जा सकता है जिसके केंद्र में एक कंपोस्टिंग बिन हो। इस बिन में रसोई का कचरा और पानी समय–समय पर भरा जाता है, जो पौधों को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को विघटित और मुक्त करता है। इसका उद्देश्य न्यूनतम प्रयास के साथ व्यवस्थित रूप से पौधों के उगाने के लिए छोटे शहरी स्थानों के उपयोग को प्रदर्शित करना है। इस प्रकार, उपरोक्त पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ ''ट्रिनिटी'' का दुर्लभ संयोजन छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्वस्थ और कीट–मुक्त और लागत प्रभावी और रासायनिक मुक्त फसल उगाने के लिए एक प्रभावी रणनीति हो सकती है।

''लाइट एंड साउंड शो'' को भी स्थानीय जनता और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया और सराहना मिली और प्रिंट मीडिया में कवरेज प्राप्त हुआ।

AADEIs का कौशल संसाधन केंद्रः (Skill Resource Centre, SRC):
प्रमाणपत्र वितरण समारोह आयोजित

SRC के तृतीय बैच के प्रशिक्षुओं के लिए द्वितीय प्रमाणपत्र वितरण समारोह 25 फरवरी 2022 को एस आर सी, आगरा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधास्वामी सत्संग सभा के सचिव श्री जी. पी. सत्संगी ने मुख्य अतिथि के रूप में की। इस अवसर पर AADEIs के अध्यक्ष डॉ एस. के. सत्संगी भी उपस्थित थे। समारोह में 31 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

AADEIs के कौशल संसाधन के समन्वयक डॉ साहब दास ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और बताया कि कौशल संसाधन केंद्र (एस आर सी) ने अब तक तीन बैचों में 67 महिला छात्रों को प्रशिक्षित किया है। इसके प्रशिक्षुओं ने बहुत ही कम समय में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण की चुनौती को बार–बार स्वीकार किया है। केंद्र प्रभारी श्री सरन श्रीवास्तव ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि यहां 'Earn while You Learn' की अवधारणा का अनुकरण किया गया है, जिससे प्रशिक्षुओं को अत्यधिक लाभ हुआ है।

प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए श्री. जी.पी. सत्संगी ने जोर देकर कहा कि अब प्रशिक्षुओं ने कौशल विकसित कर लिया है और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राहकों की वफादारी हासिल करने के लिए गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री जी.पी. सत्संगी ने प्रशिक्षुओं को रोजगार योग्य बनाने या स्व–रोजगार योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाने में AADEIs और इसके कौशल संसाधन केंद्र द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने सलाह दी कि SRC को प्रशिक्षुओं के उद्यमशीलता गुणों को और विकसित करने के लिए एक संरचित कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

इस अवसर पर AADEIs की कार्यकारी समिति के सदस्य श्री प्रेम स्वरूप ने बताया कि MSME के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रशिक्षुओं की बातचीत का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षुओं के लिए FSSAI पंजीकरण प्राप्त करने और स्वयं सहायता समूह बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

संरक्षक • प्रो. पी.के कालरा, प्रो. वी.बी. गुप्ता
संपादकीय सलाहकार • प्रो. एस. के चौहान, प्रो. जे.के. वर्मा
संपादक मंडल (अंग्रेजी अंक) • डॉ. सोनल सिंह, डॉ. मीना पायदा, डॉ. लॉलीन मल्होत्रा, डॉ. बानी दयाल धीर, श्री. राकेश मेहता
अनुवादक Attention: डॉ. स्वामी प्यारी कौड़ा
चित्रण, मुद्रण एवं ई–प्रकाशन • दयालबाग प्रेस